# भारत में कौशल प्रशिक्षण का बढ़ता वर्चस्व एवं बढ़ते रोजगार के अवसर

**पूजा सिंह**[1], शोध विद्यार्थी, शिक्षा विभाग, नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, poojasingh.aaru@gmail.com

**डॉ. संध्या कुमारी सिंह**[2], प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, sandygandhar2020@gmail.com

**सारांश**

भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए युवाओं के कौशल विकास को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। कौशल विकास से न केवल रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं बल्कि युवाओं को अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का भी अवसर मिल रहा है। देश में 2005-2017 के दौरान 2.7 मिलियन लोगों को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर मिले हैं। भारत में कौशल विकास के संवर्धन हेतु पारंपरिक दृष्टिकोण का आकलन करने की आवश्यकता है। जर्मनी, आस्ट्रेलिया और चीन ने कौशल शिक्षा पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया है जिसके फलस्वरूप वहां पर युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर मिल रहे हैं। इसी प्रकार भारत में भी कौशल विकास पर बहुत ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिस कारण आज भारत सरकार हर वर्ग के युवाओं जिनमें महिलाएं, आंशिक रूप से अपंग एवं गरीब क्षेत्र के युवाओं में कौशल विकास कर रही है जिससे अब वो अपने हुनर से एक बेहतर कल की शुरूआत कर रहे हैं। भारत सरकार ने अनेक तरह की योजनाएं आरंभ की हुई हैं तथा देश के बहुत से शिक्षण संस्थान अब इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2009 में राष्ट्रीय कौशल नीति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य देश में कौशल विकास में आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए किया गया। भारत में वर्ष 2022 तक 24 क्षेत्रों में 109.73 मिलियन कुशल मानवश्रम की आवश्यकता होगी। देश में आज बहुत क्षेत्रों को विकास हुआ है जिनमें कौशल के द्वारा ही उनका निवारण किया जा सकता है। वर्ष 2019 में सबसे रोजगार में वृद्धि पिछले 8 सालों में सबसे बेहतर रही। भारत

में युवाओं को कुशल बनाकर आज हर क्षेत्र में वृद्धि हो रही है जिससे न केवल देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं बल्कि भारतीय निर्यात में भी काफी वृद्धि हुई है। अत: कौशल विकास से देश के युवाओं के जीवन में एक नई रोशनी ला दी है।

**महत्वपूर्ण शब्द:** कौशल विकास, कौशल शिक्षा, मानवश्रम, शिक्षण संस्थान।

## 1. प्रस्तावना

भारत विश्व में अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे तेजी से उभरता हुआ देश है। कौशल शिक्षा के क्षेत्र में देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें दक्षता लेकर युवा वर्ग न केवल हुनरमंद हो रहा है बल्कि रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। इसका सबसे अच्छा असर यह हुआ है कि देश में नई नई तकनीकियों के आ जाने से युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ हैं। दक्षिण के राज्यों में की औसत आयु 29 से 31 वर्ष के बीच है जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और में उनकी औसत आयु 20-22 वर्ष के बीच है इसलिए युवाओं में कौशल विकास के प्रतिमानों को पहुंच और प्रासंगिता के आधार पर तैयार किए जाने की जरूरत है। देखा जाए तो देश में जिस तेजी से कौशल शिक्षा में रूचि दिखा रहे हैं उससे वर्ष 2030 तक कुशल श्रमशक्ति में बहुत इजाफा होगा। सरकार भी देश में कौशल विकास में काफी अहम भूमिका निभा रही है जिससे देश में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की मदद से युवाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है। यह अति आवश्यक हो गया है कि देश में कौशल शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए क्योंकि देश में बेरोजगारों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है जिसके मद्देनजर यह आवश्यक है कि देश में कौशल शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाए। कौशल शिक्षा को अपनाकर युवा वर्ग आसानी से रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकता है। किसी भी क्षेत्र में हम तभी कुशल हो सकते हैं जब कौशल विकास के साथ साथ उसमें कौशल शिक्षा को भी समावेश हो। ये दोनों आपस में पूरक हैं। कौशल विकास तभी संभव है जब उसको शिक्षा के माध्यम से समझा जाए अन्यथा उसमें दक्षता पाना अत्यंत मुश्किल है। रोजगार पाना तब ओर भी आसान हो जाता है जब उस क्षेत्र की तकनीकी जानकारी हो।

विश्व बैंक के अनुसार, भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है और भविष्य में दक्षता की मांग को देखते हुए कौशल संबंधी कार्यसूची, पर पुनर्विचार किया जाना अपेक्षित है, चूंकि विनिर्माण क्षेत्र में विश्वव्यापी स्तर पर संरचनात्मक परिवर्तन होंगे।

सरकार के सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में युवा साक्षरता दर (15-24) और वयस्क साक्षरता दर (15 वर्ष और उससे अधिक) क्रमश: 86.1 प्रतिशत और 69.3 प्रतिशत थी। सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के तहत छात्रों के लिए प्रासंगिक कौशल हासिल करने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल और प्रशिक्षण को भी शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया गया कि कौशल विकास एक गतिशील प्रक्रिया है और व्यक्तिगत कौशल को निरंतर ऊंचा उठाने में सहायक है।

प्रो. श्यामाचरण दुबे ने सामुदायिक विकास योजनाओं के भारतीय ग्रामों पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर 'भारत के बदलते हुए गाँव' (1958) पर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन में उन्होंने सामुदायिक विकास में मानव तत्व की महत्ता एवं उसकी मुख्य भूमिका को रेखांकित किया है। इसके साथ ही इसमें योजनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुए परिवर्तन तथा तत्जनित समस्याओं का मूल्यांकन किया गया है। ई.एफ. शूमाकर ने अपनी पुस्तक 'स्माल इज ब्यूटीपुफल : ए स्टड़ी ऑफ इकोनॉमिक्स इज ए पिपल मैटर्ड़' (1973) में पाश्चात्य आर्थिक नीति की आलोचना की क्योंकि बड़े उद्योगों द्वारा प्रकृति का दोहन होता है और सतत विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन्होंने लघु उद्योगों एवं आम जन की आत्मनिर्भरता पर बल दिया तथा पर्यावरण हितैषी सतत विकास की बात की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा नवम्बर, 2010 में कुशल कार्यबल पर एक रिपोर्ट 'ए स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर स्ट्रांग, सस्टेनेबल एंड बैलेंसड़ ग्रॉथ : ए G20 ट्रेनिंग स्ट्रेटजी' में कौशल विकास के प्रशिक्षण की तकनीक ओर नवोन्मेषण की व्यापक अवधारणा प्रस्तुत की तथा यह दर्शाने का प्रयास किया कि किस प्रकार कुशल कार्य बल धारणीय विकास में योगदान दे सकता है। मैकलीन, स्पर्ट, जगन्नाथन, शान्ति, सारवी एवं जोको द्वारा सम्पादित पुस्तक 'स्किल्स डेवलपमेंट फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन डेवलपिंग एशिया-पेसिफिक' में एशिया प्रशांत क्षेत्र में कौशल विकास से संबंधितमुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है साथ ही गांव से शहरों की और पलायन कर रहे चीन के मजदूरों की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। फिक्की द्वारा इंडिया इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर (2012) में 'स्किल्स फॉर ऑल न्यू एप्रोच्स टू स्किलिंग इंडिया' रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कौशल तक पहुँच में सुधार एवं कौशल आधारित शिक्षा के दृष्टिकोण में परिवर्तन जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई है।

**भारत में शुरू की गई कौशल विकास संबंधी योजनाएं एवं मिशन निम्नलिखित हैं:**

(1) **राश्ट्रीय कौशल विकास मिशन**

इस मिशन की शुरूआत 15 जुलाई, 2015 को कौशल दिवस के अवसर पर की गई। इसके तहत 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु क्षमताओं का सृजन किया जाएगा। इसके तहत 20 केंद्रीय मंत्रालय एवं विभाग कौशल विकास कार्यक्रम में लगे हैं जिन्होंने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के कौशलीकरण लक्ष्य को 125.69 और 117.50 लाख अभ्यर्थियों की तुलना में क्रमश: 104.16 और 60.32 लाख अभ्यर्थियों को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया है।

(2) **कौशल भारत कुशल भारत मिशन**

कौशल भारत मिशन को अन्तर्गत मोदी सरकार ने गरीब व वंचित युवाओं प्रशिक्षित करके बेरोजगारी की समस्या और गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इस मिशन का उद्देश्य उचित प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं में आत्मविश्वास को लाना है जिससे की उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इस योजना के माध्यम से सरकारी, निजी और गैर-सरकारी संस्थानों के साथ साथ शैक्षिक संस्थाएं भी सम्मलित होकर कार्य करेंगी।

(3) **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)**

यह योजना 15 जुलाई, 2015 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) कौशल विकास और उद्यमिता के नए मंत्रालय (MSDE) के परिणामस्वरुप शुरू कि गई प्रमुख कौशल प्रशिक्षण योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं की एक बड़ी संख्या को कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए जुटाना और अपनी आजीविका कमाने के लिए सक्षम बनाना है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों को उच्च गुणवत्ता और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम कर उनकी उत्पादकता को बढ़ावा देगा।

**(4) प्रधानमंत्री कौशल युवा योजना (पीएमवाईवाई)**

यह योजना 9 नवंबर, 2016 को शुरू की गई। इसके योजना के अंतर्गत 2016-17 से 2020-21 तक विभिन्न ट्रेडों में 14.5 लाख युवाओं को कौशल क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। इस योजना में उद्यमशीलता शिक्षा

और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए 3050 संस्थान जिसमें उच्च शिक्षा के 2200 संस्थान, 300 स्कूल, 500 आईटीआई और 50 उद्यमिता विकास केंद्र मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से शामिल किए हैं।

**(5) प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई)**

इस योजना को 14वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान 9 जून, 2017 में शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य विदेश में रह रहे भारतीय युवाओं की कौशल विकास क्षमता में संवर्धन करना है। इस योजना के तहत 9 राज्यों में 16 भारत-अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं।

**(6) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई)**

इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 25 सितंबर, 2014 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य रोजगार से जुड़ी आबादी में वैश्विक कमी के कारण उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय अवसरों का लाभ पाने के लिए गरीब ग्रामीण युवाओं को सक्षम बनाना है।

इसमें 18-35 आयु वाले ग्रामीण युवाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में 3,6,9 और 12 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसके तहत 1.49 लाख अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। इस योजना में 24 राज्यों के 617 जिले शामिल हैं।

**(7) "हिमायत" योजना**

जम्मू के युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल विकास के लिए मंत्रालय द्वारा 21 अगस्त, 2011 को श्रीनगर में यह योजना शुरू की गई। इसका लक्ष्य 5 वर्ष में 18-35 आयु के एक लाख युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना है।

**(8)"रोशनी" योजना**

देश में वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 27 जिलों में 18-35 आयु के गरीब युवाओं को लाभांवित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 10/06/2013 को इस योजना की शुरूआत की। इस योजना में युवाओं को

योग्यताओं के अनुरूप 6,9 और 12 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा 3 वर्ष में 50,000 युवाओं को कवर करने का लक्ष्य है। जिसमें कम से कम 40% महिलाएं हैं।

## 2014 से 2017 के दौरान दीर्घाअवधि कौशल प्रणालियों में हासिल की गई उपलब्धियां

| दीर्घावधि प्रशिक्षण | मई, 2014 के आंकड़े | मई, 2017 के आंकड़े | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| दीर्घावधि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या | 10,750 | 13,353 | 24% की वृद्धि |
| दीर्घावधि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों की संख्या | 19.82 लाख | 28.52 लाख | 44% की वृद्धि |
| दीर्घावधि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या | 17.80 लाख (2013-14 के आंकड़े) | 22.40 लाख (2016-17 के आंकड़े) | 26% की वृद्धि |

***स्रोत : योजना पत्रिका***

## 2014 से 2017 के दौरान अल्पावधि कौशल प्रणालियों में हासिल की गई उपलब्धियां

**एनएसडीसी के जरिय अल्पावधि शुल्क आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भी इजाफा हुआ।**

1. मई, 2014 से मई, 2017 के दौरान प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या में 85.9% की वृद्धि दर्ज की गई।
2. 2013-14 से 2016-17 के बीच उम्मीदवारों की संख्या में 71% अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई।

## कौशल शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याएं

हाल ही में शारदा प्रसाद समिति (एसपीसी) ने "अपर्याप्त इंडस्ट्री इंटरफेस" को भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली के समक्ष मौजूद प्रमुख मसलों में से एक करार दिया है। वीईटी कोर्सेज के डिजाइन और पाठ्यक्रम तैयार करने में उद्योग जगत से पर्याप्त इनपुट नहीं लिए जाने के कारण अक्सर वहां सिखाए जाने वाले कौशल नियोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते।

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में उद्योग जगत को शामिल नहीं किया जाना कौशल विकास क्षेत्र के समक्ष वर्तमान में आ रही प्रमुख चुनौतियों में से एक है। इसमें डिलिवरी, संस्थाओं के प्रबंधन और पाठ्यक्रम तैयार करने में उद्योग को ज्यादा शामिल नहीं किया जाना शामिल है।

आईआईटी, बेंगलुरू द्वारा कराए गए एक अध्ययन में पाया गया कि संस्थान प्रबंधन समितियों (आईएमसी) में नियोक्ता की भागीदारी सीमित है। इन समितियों का गठन 2007-08 में उद्योग जगत के निकायों के रूप में किया गया था और इन्हें नए कोर्स, कोर्स के पाठ्यक्रम शुरु करने तथा प्रशिक्षकों को नियुक्त करने का जिम्मा सौंपा गया था। टीमलीज़ सर्विसिज द्वारा जारी रिपोर्ट में पाया गया कि राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) उद्योग जगत की जरूरतों के अनुरूप कोर्स की रूपरेखा और पाठ्यक्रम का तालमेल बिठाने में समर्थ नहीं रही। सर्वेक्षण में शामिल किए गए 78 प्रतिशत से ज्यादा छात्रों और 66 प्रतिशत नियोक्ताओं ने इन संस्थाओं और इनके द्वारा संचालित किए जा रहे कोर्सेज को औसत या खराब बताया है। एक नए रास्ते की रूपरेखा तैयार किए जाने की जरूरत है, जो वीईटी के डिजाइन और डिलिवरी में उद्योग जगत को ज्यादा प्रभावी रूप से शामिल करे। इसकी जिम्मेदारी सरकार और साथ ही साथ निजी क्षेत्र, दोनों को उठानी होगी। उद्योग जगत के प्रतिनिधित्व के बगैर वीईटी व्यवस्था तैयार करना बेकार है।

दूसरा, देश में कौशल प्रशिक्षण के प्रमाणन मापदंड तय करने की तत्काल जरूरत है। वर्तमान में, डीजीटी और एनएसडीसी के साथ-साथ करीब 20 मंत्रालय व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं। उपलब्ध कार्यक्रमों के बारे में स्पष्टीकरण के अभाव और विविध कार्यक्रमों के प्रावधान के कारण नियोक्ताओं को इस प्रशिक्षण की समग्रता और गुणवत्ता पर विश्वास नहीं है।

पाठ्यक्रम और प्रमाणन के मापदंड तय करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत गुणवत्ता या क्वालिटी पैक्स के आकलन की जिम्मेदारी औद्योगिक इकाइयों को सौंपे, ताकि उन्हें उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सके। इसके बाद यह पता लगाने के लिए नियमित रूप से तीसरे पक्ष द्वारा इनका आकलन किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षण संस्थानों या प्रदाताओं द्वारा एनएसक्यूएफ का पालन किया जा रहा है या नहीं।

## कौशल संबंधी चुनौतियों का समाधान

1. प्रशिक्षण की गुणवत्ता में में सुधार करना यह बहुत ही अहम समस्या है जिसके अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने प्रशिक्षण में **ग्रेडिंग** में सुधार किया है साथ ही साथ **प्रत्यायन और सम्बद्धता मानदंड** को सुदृढ़ किया है एवं **व्यापक पाठ्यक्रम सामग्री** को अपग्रेड करके उसमें सुधार किया है।
2. कौशल संबंधी जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह रोजगार दिलाने में कितना सहायक होगा यह भी बहुत ही अहम विषय है अर्थात वर्तमान में उस कौशल प्रशिक्षण की कितनी मांग है। अत: इस समस्या को देखते हुए संस्थान कौशल संबंधी उन्हीं प्रशिक्षणों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो रोजगार परक हैं।
3. युवा वर्ग कभी कभी यह नहीं समझ पाते कि उन्हें किस प्रशिक्षण को चुनना है यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए संस्थान उन्हें इस बारे में सही ढंग से जानकारी देने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

## निष्कर्ष

कौशल शिक्षा के माध्यम से न केवल युवाओं में छिपी प्रतिभा को उजागर किया जा सकता है बल्कि उन्हें एक अच्छे रोजगार दिलाने में मदद भी आसानी से हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कौशल शिक्षा को ध्यान में रखकर उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इससे भारत में बेरोजगारी की समस्या का निवारण होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी, गरीब समाप्त होगी, भारत में छिपी हुई योग्यता को बढ़ावा मिलेगा, राष्ट्रीय आय के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से यह सामने आया है कि कुशल व्यक्ति सही दिशा में बढ़ रहा है।

***References:***

Dube, S.C 1955: Indian village, Haraper colins books, New York.

Dube,S.C 1958: India's Changing Village, Allied Publishers Pvt. Limited

Schumacher, E.F 1973: Small is Beautiful:A Study of Economics As If People Mattered,Blond &Briggs

Gulati, J.S 1974: Changing Occupational Pattern, NCERT, New Delhi

Smelser, Neil J 1998: The Sociology of Economic Life, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi

Sorokin, Pitirim 1978: Contemporary Sociological Theories, Kalyani Publishers Delhi.

Ahuja, Ram 2008: Research Methods, Rawat Publication, New Delhi

Dooley, David 2001: Social Research Methods , Prentice Hall New Jursi

Dhamija, Jasleam 1979: Indian Folk Arts and Crafts, NBT, New Delhi

Singh, Yogendra 1997: Social Stratification and change in India, Manohar Publication, New Delhi

Singh. Yogendra 1973: Modernization of Indian traditions:A systemic Study of Social Change, Thomson Press

Fukuyama, Francis 1992: The End of History & The Last Man, Free press

Gandhi, M.K. 1938: Hind Swaraj, Ahmedabad: Navajivan publications.

Giddens, Anthony 2002:Runaway world: How Globalization is Reshaping our Lives, Profile Books

Gupta, Dipankar 2000: Mistaken Modernity: India Between Worlds, Harper Collins, New Delhi

Hanumanth Rao, C.H. 2005: Agriculture, Food Security, poverty and Environment: Essays on post-Reform India, Oxford Journals, New Delhi

Oommen, T.k. 2006: Bringing Gandhi Back into Independent India", Gandhi Marg, Val, 28, N0. 4, January- March, pp: 433-443

Jena, Pradeep Kumar 2008: "Globalisation and Indian handicrafts: Quest for a Gandhian way" Gandhi Marg, Val-30, No-1, April June: PP: 103-119

Singh, Jatinder 2017: Vikas Gatha: Skill Development Innovation youth empowerment, Yojana Magzine, May, pp:35

National Skill Development Corporation (NSDC)

Director General of Traing Deptt. (DGT)

***Reports:***

FICCI (IITF 2012), Skills For All New Approaches to Skilling India
ILO, Geneva: 2010 (Report) A Skilled Workforce for Strong, Sustainable and Balanced Growth
Maclean, Rupert & Jagannathan,Shanti &Sarvi, Jouko [edit] Skills Development For Inclusive & Sustainable Growth in Developing Asia-Pacific Economic Survey 2014-2015Govt.of India,New Delhi

***Newspaper and Magazine:***

Special Issue Yojana, Oct. 2015. Skill development
Special Issue Kurushetra (Hindi) Sep. 2017. Gramin Vikas main Kaushal Vikas
Kumar, Vivek & Kapoo, Radhika: 2015"The nuts and bolts of Skill development"The Hindu,23 Mar.
Chakrabarti, Rajesh & Parkesh, Kushal Sagar: 2016 " Skill India or kill India: How to Cope with the impending demographic deluge." Times of India. 7th July
"Internship enhance skills": 2018. Rashtriya Sahara. 25th June.